

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2025/16

अपील संख्या - 09/25

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी छीपा मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर वसीयती वारिस मृतका हरिप्रिया उर्फ लाड बाई पुत्री केसरलाल पत्नि रामकुमार जाति ब्राह्मण।

अपीलांत



बनाम

श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नि लोकेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मिश्र मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर

2. श्रीमती इन्द्रा पुत्री मनमोहन पत्नि रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हिन्दुपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
3. श्रीमती मंजू पुत्री मनमोहन पत्नि रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेसपो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 74/22 निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री रघुनन्दन सिंह राजावत

अभिभाषक रेसपो श्री आशीष जैन

दिनांक 29.07.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीयां/रेसपो न0 1 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयां की कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 872 रकबा 0.08 है0, 873 रकबा 0.01 है0, 874 रकबा 0.02 है0, 875 रकबा 0.16 है0, 876 रकबा 0.12 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.39 है0 कस्बा सवाई माधोपुर में स्थित है। प्रार्थीयां ने उक्त आराजी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साधिकार नियमानुसार बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को खरीदकर कब्जा मालिकाना पाया है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीयां के खातेदारी में इन्द्राजित है। उक्त आराजी का साबिक ख0न0 402 रकबा 12 विस्वा, 403 रकबा 6 विस्वा, 404 रकबा 8 विस्वा, 405 रकबा 5 विस्वा है। अप्रार्थीयां डिकीदार हरिप्रिया उर्फ लाडबाई ने एक राजस्व वाद वर्ष 1981 में वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार उदघोषित करने, स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व वादग्रस्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मनमोहन से दिलवाने बाबत किया था जो राजस्व वाद संख्या 618/1981 उनवानी हरिप्रिया उर्फ लाडबाई बनाम मनमोहन न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर की अदालत से दिनांक 14.12.83 को निम्नानुसार विवेचन के साथ खारिज किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



फलस्वरूप उक्त विवेचनो के अनुसार वादिया का वाद मियाद बाहर होने के अलावा उसके नियमित कब्जे काश्त बाबत भी कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण दावा वादिया खारिज किया जाता है " उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के उक्त निर्णय के विरुद्ध हरिप्रिया उर्फ लाडबाई ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जो 12.6.87 को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात विषयक संदिग्धता के पुनः न्यायिक निर्णयार्थ उप जिलाधीश सवाई माधोपुर को रिमाण्ड की गई। जिलाधीश के वाद प्रकरण पुन उप जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष लंबित रहते हुए मनमोहन का देहान्त हो जाने पर अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 को बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर लिया गया और जबाब दावा पेश करने के अवसर बाबत विधिक आपत्ति के निस्ताणार्थ प्रकरण लंबित रहते ही उक्त 1981 का राजस्व वाद 4.7.95 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जो प्रकरण नैतिक हो गया। वादग्रस्त आराजी माफीदार केसरलाल पुत्र प्रभूसहाय के नाम थी जो कालान्तर में केसरलाल के देहान्त पर उसकी बेवा श्रीमती नैनी के नाम माफी में इन्द्राजित हुई। इसके खातेदारी कालम में भी कल्याण पुत्र श्री बिहारी का नाम रहा है जो कल्याण पुत्र श्री बिहारी ही आरंभ से अन्त तक इस पर काबिज होकर सतत काश्त करता रहा है। और सम्वत 2021 से 2024 के दौरान राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड रिजग्शन एक्ट 1955 के प्रभाव में आने पर भूमि माफी से रिज्यूम होकर कल्याण पुत्र बिहारी के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने पर इसी के कब्जा काश्त खातेदारी में इन्द्राजित हो गई। श्री कल्याण पुत्र श्री बिहारी लाल का वर्ष 1971-72 में देहान्त हो जाने पर यह भूमि 2.3.72 के नामा० आदेश से कल्याण के भ्राता रामदास के नाम इन्द्राजित हो गई और रामदास का कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर निर्बाध चलता रहा है। वादग्रस्त आराजी पर और वर्ष 1977 में श्री रामदास के देहान्त पर उक्त आराजी अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 के पिता मनमोहन के नाम जरिये नामा० विरासत दिनांक 31.5.77 को इन्द्राजित हुई। तदपरान्त मनमोहन के देहान्त पश्चात वादग्रस्त आराजी 2.8.97 के नामा० आदेश से अप्रार्थीयां 2 व 3 के नाम कब्जा काश्त खातेदारी में दर्ज हुई है जिस पर इन्ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा साधिकार नियमानुसार निर्बाध बदस्तूर सतत रहा है। जिनसे प्रार्थीयां ने उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिफल क्रय कर कब्जा खातेदारी प्राप्त किया है। जब से ही प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार सदभावी क्रेता काबिज होकर सतत निर्बाध काश्त करती चली आ रही है और इसमें निर्मित हिस्से पर प्रार्थीयां का ही कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अप्रार्थीयां हरिप्रिया उर्फ लाडबाई जरिये राजेन्द्र प्रसाद अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त राजस्व इन्द्राजात व कब्जा की सत्यता व 1981 के पूर्व के राजस्व वाद में असफलता की सत्यता को छिपाकर न्यायालय में नवीन वाद 13.11.2000 को पेश किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत दिनांक 19.5.2003 को डिक्री किया गया है और राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 17.11.2003 को अपील खारिज कर पुष्ट किया गया है और इसके विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में पेश द्वितीय अपील भी दिनांक 9.1.20 को खारिज की जाकर इस न्यायालय के आदेश को पुष्ट किया गया है। इस दौरान राजस्व मंडल अजमेर में भी मृतका हरिप्रिया उर्फ लाडबाई के बसीयती वारिस के रूप में राजेन्द्र प्रसाद रिकार्ड पर बजरिये आदेश दिनांक 24.8.19 आया है जो पूर्णतया जाली, फर्जी व कूटरचित बसीयत के आधार पर बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर आया है। राजेन्द्र द्वारा कथित वसीयत दिनांक 8.9.2000 का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मुख्तारनामा भी राजेन्द्र के पक्ष का है जबकि इसके वाद दावा स्वयं हरिप्रिया उर्फ लाडबाई के स्वयं के नाम से दिनांक 13.11.2000 को पेश हुआ जो इन दस्तावेजों को फर्जी कूटरचित जाली संदिग्ध ताईद करता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीयां को उक्त राजस्व वाद से व इसकी प्रगति से अनभिज्ञ रखा है। प्रार्थीयां सदभावी सप्रतिफल केता है। मृतक हरिप्रिया उर्फ लाडबाई की फर्जी वसीयत के आधार पर राजेन्द्र उक्त वाद को डिकी की इजराय में प्रार्थीयां के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त राजस्व इन्द्राजात में माने मजाहमत कारित करता है। प्रार्थीयां को भूमि से बेदखल करने की धमकी देता है। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होना जाहिर कर रहे हैं। इस पर भी जहाँ तक राजस्व रिकार्ड तब्दील करने का प्रश्न है तो वर्तमान में इन्द्राजात प्रार्थीयां के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसे सुने बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना डिकी व निर्णय दिनांक 19.5.2003 की उक्त इजराय संख्या 2/20 पेशी दिनांक 6.10.2020 में प्रार्थीयां के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रश्नगत निर्णय व डिकी प्रार्थीयां के विरुद्ध निष्पादनीय आवद्धकारी नहीं है। जिसकी आड में प्रार्थीयां को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है ना ही प्रार्थीयां का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जा सकता है। क्योंकि प्रश्नगत डिकी में प्रार्थीयां को सुना ही नहीं गया है। लिहाजा यह उज्रदारी आपत्ति दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि उप जिलाधीश सवाई माधोपुर दिनांकित 19.5.03 बमुकदमा उनवानी हरिप्रिया बनाम श्रीमती इन्द्रा मु0न0 125/2000 निर्णय दिनांक 17.11.03 एवं राजस्व मंडल अजमेर का निर्णय दिनांक 9.1.20 की आड में प्रार्थीयां के कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज में माने मजाहमत मदालखत कारित ना करे और इनकी इजराय में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण निर्णय व डिकी उप जिलाधीश सवाई माधोपुर दिनांकित 19.5.03 मु0न0 125/2000 एवं प्रथम अपील निर्णय व डिकी राजस्व अपील प्राधिकारी निर्णय दिनांक 17.11.03 एवं राजस्व मंडल अजमेर का निर्णय दिनांक 9.1.20 की आड में प्रार्थीयां कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज में माने मजाहमत नहीं करे मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीयां /रेस्प0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि जो उज्रदारी वाद रेस्प0 संख्या 1 ने अपनी अदालत के निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.5.03 जो राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय डिकी दिनांक 17.11.03 तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निर्णय व डिकी

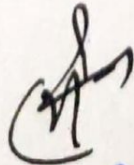
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 9.1.20 बहाल रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.3.2003 को रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर हरिप्रिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। जिसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय जैर निर्णय कर अहम भूल की है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीयां रेस्पो0 द्वारा जैर विवादित आराजीयात दौराने अपील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 से खरीद की है और रेस्पो0 संख्या 2 व 3 विक्रेता है जिनकी अपीले खारिज हो चुकी है जा जैर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर दिनांक 1.11.11 अपीलार्थी के विरुद्ध कानून पठनीय नहीं होने जैर विक्रय पत्र प्रभावहीन व शून्य है। जिसके बाबजूद जैर निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है सो जैर निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि निर्णय दिनांक 19.3.03 व ता अपील आराजीयात मण्डल अजमेर दिनांक 9.1.20 द्वारा बहाल रखा गया है सो रेस्पो0 संख्या 2 व 3 जैर निर्णय से आवद्ध होने के साथ साथ परचेजर रेस्पो0 संख्या 1 पर भी बाइन्डिंग है तथा जैर निर्णय व डिक्री से आवद्ध होने के कारण किसी प्रकार की उज्जदारी अथवा वाद करने से प्रवारित होने के कारण वाद पत्र उज्जदारी ग्रहण योग्य ही नहीं था जिसे मनमाने ढंग से अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान धारा 52 टी पी के विरुद्ध जैर निर्णय पारित किया जो इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 19.3.03 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्ज जैर विवादित आराजीयात अपीलार्थी वसीयत हरिप्रिया की माता नेनी देवी के नाम खातेदारी दर्ज थी जो कल्याण पुत्र बिहारी के नाम किस विधिक अधिकार से दर्ज की गई जिसे रेस्पो0 संख्या 2 व 3 साबित करने मे असफल रही है। यह तथ्य अपीलीय हाजा के निर्णय दिनांक 17.11.2003 मे अपने फैसले मे अंकित किया कि अपीलार्थीगण यानि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कमश इन्द्रा व मंजू का वैध अधिकार किसी प्रकार है यह साबित नहीं कर पाई कि उनका विवादित आराजी जो मु0 नेनी पत्नि केसर की भूमि है किस प्रकार इन्ट्रेस्ट रखते है महज बन्दोबस्त द्वारा मनमोहन की खातेदारी मे अंकित हो जाने से मनमोहन के वारिसान को विधिक अधिकारी नहीं माना जा सकता। सेटलमेंट को पूर्व के अंकनो को ही रिपीट करने का अधिकार है उन्हे अपने स्तर पर अंकन करने या उन्हे कलमजन करने का अधिकार नहीं है बाबजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विवेक का उपयोग किये तथा विधि के प्रावधानो के विरुद्ध जैर निर्णय पारित किया जो खारिज किये जाने योग्य है। जैर विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 इन्द्रा,मंजू का कोई कब्जा नहीं था यदि कब्जा होता तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे किये गये विक्रय पत्र मे मौके पर बने हुए मकानात की नाप सही अंकित होती। विक्रय पत्र के पेज न0 6 की पंक्ति संख्या 10 व 11 मे दर्ज 8 गुणा 8 का पटटी पोश कमरा व 15 गुणा 8 का पटटी पोश बरामदा व 8 गुणा 8 फीट टीन पोश बना हुआ है। जबकि मौके पर 9.5 गुणा 9 फीट का कमरा बना हुआ है कमरा व बरामदा की लम्बाई 32 फीट 10 इंच है जबकि विक्रय पत्र के अनुसार कमरा व बरामदा की लम्बाई 23 फीट लिखी हुई है इससे स्पष्ट साबित होता है कि इन्द्रा,मंजू यानि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का दिनांक 1.11.2011 को या उससे पूर्व कब्जा ही नहीं था बल्कि अपीलार्थी का कब्जा था। यदि रेस्पो0 संख्या 1 का जैर आराजीयात पर कब्जा होता तो अपीलार्थी उसे उस समय चल रही अपील मे बतौर रेस्पो0 बनाता इससे भी यह साबित है कि रेस्पो0 का कब्जा नहीं था

राजेश्वर अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिवक्ता सेल डीड रेस्पों को जैर आराजीयात का विवाद यानि अपील चल रही होना ज्ञात था और अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन था सो जैर आराजीयात रेस्पों संख्या 2 व 3 जैर आराजीयात का विक्रय नहीं कर सकती थी इसलिए जैर आदेश धारा 52 टी पी एक्ट का उल्लंघन होने से जैर आदेश खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पों संख्या 2 व 3 का जैर आराजीयात पर विधिक अधिकार एवं कब्जा होता तो कोस अपील पेश कर सकती थी सो नहीं की गई इससे यह साबित है कि रेस्पों संख्या 2 व 3 का जैर विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का विधिक हक व कब्जा नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर आदेश पारित कर अहम भूल की है इसलिए जैर निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों का कब्जा नहीं होते हुए मात्र जमाबंदी में नाम दर्ज होने के जैर आदेश पारित कर अहम भूल की है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं कर अहम भूल की सो जैर आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.24 खारिज फरमाया जावे। अपीलांत अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

रेस्पों के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख०न० 872 रकबा 0.08 है०, 873 रकबा 0.01 है०, 874 रकबा 0.02 है०, 875 रकबा 0.16 है०, 876 रकबा 0.12 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.39 है० कस्बा सवाई माधोपुर में स्थित है। प्रार्थीयां ने उक्त आराजी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साधिकार नियमानुसार बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को खरीदकर कब्जा मालिकाना पाया है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीयां के खातेदारी में इन्द्राजित है। उक्त आराजी का साबिके ख०न० 402 रकबा 12 विस्वा, 403 रकबा 6 विस्वा, 404 रकबा 8 विस्वा, 405 रकबा 5 विस्वा है। रेस्पों/अर्चना ने विवादित आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिफल अदा कर खरीद किया है इस प्रकार प्रार्थीयां/रेस्पों संख्या 1 सदभाविक क्रेता है। अपीलांत अधिवक्ता का बार बार कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर रेस्पों/अर्चना का कब्जा नहीं है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो अपीलांत के उक्त कथन की पुष्टि करता हो जबकि सत्यता यह है कि विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पों/प्रार्थीयां अर्चना का क्रय दिनांक से निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी माफीदार केसरलाल पुत्र प्रभूसहाय के नाम थी जो कालान्तर में केसरलाल के देहान्त पर उनकी बेवा श्रीमती नेनी के नाम माफी में इन्द्राजित हुई। इसके खातेदार कालम में श्री कल्याण पुत्र बिहारी का नाम रहा है जो कल्याण पुत्र बिहारी ही आरंभ से अन्त तक इस पर काबिज होकर सतत काश्त करता रहा है और सम्वत 2021 से 2024 के दौरान राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड रिजमंशन एक्ट 1955 के प्रभाव में आने पर भूमि माफी से रिज्यूम होकर कल्याण पुत्र बिहारी के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने पर इसी के कब्जा काश्त खातेदारी में इन्द्राजित हो गई। कल्याण पुत्र बिहारी का वर्ष 1971-72 में देहान्त हो जाने पर यह भूमि 2.3.72 के नामा० आदेश से कल्याण के भ्राता रामदास के नाम इन्द्राजित हुई और रामदास का कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज बदस्तुर चलता रहा है। वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1977 में रामदास के देहान्त पर उक्त आराजी अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 के पिता मनमोहन के नाम बजरिये नामा० विरासत दिनांक 31.5.77 इन्द्राजित हुई। तत्पश्चात मनमोहन के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी 2.8.97 के नामा० आदेश से अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 के नाम



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी दर्ज रहते समय ही प्रार्थीयां अर्चना द्वारा विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय किया गया है। तथा कय दिनांक से ही विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त बदस्तुर लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 द्वारा भी सहमति प्रकट की गई है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई प्रमाण पेश नही किया है ना ही इस न्यायालय मे पेश किया गया है। विवादित आराजीयात की वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी रेस्पो/प्रार्थीयां अर्चना के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि से प्रार्थीयां को अपीलांट द्वारा जबरन किसी समक्ष न्यायालय मे आदेश के बिना बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 को अपूर्णनीय क्षति होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व रिकार्ड का विधिक रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीयां अर्चना द्वारा भूमि वर्तमान खसरा न0 आराजी ख0न0 872 रकबा 0.08 है0, 873 रकबा 0.01 है0, 874 रकबा 0.02 है0, 875 रकबा 0.16 है0, 876 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.39 है0 कस्बा सवाई माधोपुर को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साधिकार नियमानुसार बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को खरीद किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात से अपीलांट द्वारा प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 को बेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीयां/अर्चना का कब्जा नही है ना ही विक्रेता इन्द्रा व मंजू का था। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात को प्रार्थीयां अर्चना द्वारा प्रकरण के अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए कय किया गया है। जो नल एण्ड बोर्ड है। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमे हक एवं अधिकारो का निर्धारण नही होता है। चूकि: विवादित आराजीयात की वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी प्रार्थीयां अर्चना के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय किया गया है इस प्रकार प्रार्थीयां उक्त आराजीयात की सदभावी क्रेता साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीयां/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित होता है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा होने के संबंध मे अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होने से अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा 74/22 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(लक्ष्मी कान बालोत)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर